



Exam Genius

India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK RAILWAY Exam

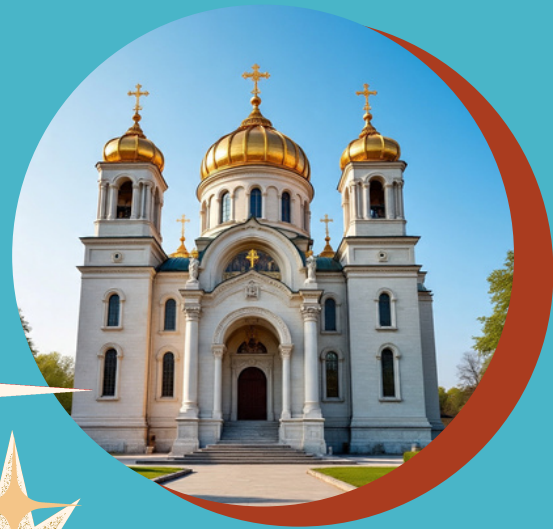


BANKING AND FINANCIAL AWARENESS

28 DEC - 3 JAN 2026

5TH WEEK OF DECEMBER

50+ MCQ
with detailed
explanation



- Banking & finance
- Banking Facilities
- Banking Appointment
- Banking Agreement



Ques: By how much did India's foreign exchange reserves increase in the latest data released by the RBI?

RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में कितनी वृद्धि हुई?

- A) USD 1.03 billion
- B) USD 0.89 billion
- C) USD 0.75 billion
- D) USD 1.25 billion
- E) USD 1.50 billion

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- India's foreign exchange reserves increased by USD 1.03 billion, taking the total reserves to USD 687.26 billion. The data was released by the Reserve Bank of India (RBI).
- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 1.03 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जिससे कुल भंडार 687.26 अरब डॉलर हो गया। यह आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा जारी किए गए।
- The increase followed a decline in the previous week, indicating a balanced recovery in forex reserves.
- यह वृद्धि पिछले सप्ताह की गिरावट के बाद दर्ज की गई, जो संतुलित सुधार को दर्शाती है।
- Foreign Currency Assets (FCA) remained the largest component of India's forex reserves.
- विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA) भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा बनी रहीं।
- Changes in FCA are mainly due to valuation effects arising from movements in the Euro, Pound Sterling, and Japanese Yen against the US Dollar.
- FCA में बदलाव मुख्य रूप से यूरो, पाउंड स्टर्लिंग और जापानी येन की अमेरिकी डॉलर के मुकाबले विनिमय दर में उतार हैं। होते कारण के चढ़ाव-
- The rise in reserves was primarily supported by an increase in gold reserves and gains in Special Drawing Rights (SDRs).
- भंडार में वृद्धि मुख्य रूप से स्वर्ण भंडार और विशेष आहरण अधिकार (SDR) में बढ़ोतरी के कारण हुई।
- India's forex reserves include Foreign Currency Assets (FCA), Gold Reserves, Special Drawing Rights (SDRs), and the RBI's reserve position with the International Monetary Fund (IMF).

- भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA), स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDR) और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ RBI की आरक्षित स्थिति शामिल होती है।

**Ques: Canara ai1Pe, recently in news, is launched by which bank?
हाल ही में समाचारों में रहा Canara ai1Pe किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है?**

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक
- D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा
- E) Union Bank of India / यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

Answer: Option C

Explanation / व्याख्या:

- Canara ai1Pe has been launched by Canara Bank.
- Canara ai1Pe को केनरा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है।
- It allows users to link savings or current accounts from any bank to make and receive UPI payments.
- यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी बैंक के बचत या चालू खाते को लिंक करके UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है।

About Canara Bank :

- Established : 1906
- HQ : Bengaluru
- MD & CEO : K Satyanarayana Raju
- Tagline : Together We Can

Ques: Which bank launched the 'Digital Merchant Cash Advance Loans' for MSMEs in India?

भारत में MSMEs के लिए 'Digital Merchant Cash Advance Loans' किस बैंक ने लॉन्च

किया?

- A) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- B) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- C) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
- D) SBI / एसबीआई
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Axis Bank Limited, a leading private sector lender in India, launched a new digital loan product called 'Digital Merchant Cash Advance Loans' for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).
- भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक लिमिटेड ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए 'Digital Merchant Cash Advance Loans' नामक नया डिजिटल लोन उत्पाद लॉन्च किया।
- The product is designed to meet the cash flow requirements of small merchants, offering an unsecured credit facility ranging from Rs 2 lakh to Rs 20 lakh.
- यह उत्पाद छोटे व्यापारियों की नकदी प्रवाह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो 2 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक की अनसिक्योर्ड क्रेडिट सुविधा प्रदान करता है।
- The loan features an Everyday Installment (EDI) system for flexible repayment.
- इस लोन में लचीले पुनर्भुगतान के लिए Everyday Installment (EDI) सिस्टम की सुविधा है।

About Axis Bank :

- Established : 1993
- HQ : Mumbai, Maharashtra
- Chairman : Rakesh Makhija
- MD & CEO : Amitabh Chaudhary
- Tagline : Badhti Ka naam Zindagi

Ques: Who has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of Canara Bank?

कनारा बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (MD & CEO) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) K Satyanarayana Raju / केराजू सत्यनारायण .
- B) Brajesh Kumar Singh / ब्रजेश कुमार सिंह
- C) Bhanu Pratap Sharma / भानु प्रताप शर्मा
- D) Atanu Kumar Das / अतनु कुमार दास
- E) Rajneesh Karnatak / रजनीश कर्नाटक

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Brajesh Kumar Singh has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer (MD & CEO) of Canara Bank.
- ब्रजेश कुमार सिंह को कनारा बैंक का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- He has replaced K. Satyanarayana Raju in this position.
- उन्होंने के.के. राजू सत्यनारायण .
- Prior to this appointment, Brajesh Kumar Singh was serving as an Executive Director at the state-owned Indian Bank.
- इस नियुक्ति से पहले ब्रजेश कुमार सिंह सार्वजनिक क्षेत्र के इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत थे।
- The appointment was made based on the recommendation of the Financial Services Institutions Bureau (FSIB).
- यह नियुक्ति वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) की सिफारिश पर की गई है।
- The Financial Services Institutions Bureau (FSIB) is responsible for selecting the chiefs of public sector banks and insurance companies. The Chairman of FSIB is Bhanu Pratap Sharma.
- वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (FSIB) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करता है। FSIB के अध्यक्ष भानु प्रताप शर्मा हैं।

Ques: Which fintech company received the TPAP license from NPCI to offer UPI services through its platform?

कौन सी फिनटेक कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से UPI सेवाएँ प्रदान करने के लिए NPCI से TPAP लाइसेंस मिला?

- A) Paytm / पेटीएम
- B) PayNearby / पेनियरबाय
- C) PhonePe / फोनपे
- D) Google Pay / गूगल पे
- E) BharatPe / भारतपे

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- PayNearby, a leading Indian fintech company, secured the Third-Party Application Provider (TPAP) license from the National Payments Corporation of India (NPCI), enabling it to offer Unified Payments Interface (UPI) services directly through its own platform.
- प्रमुख भारतीय फिनटेक कंपनी PayNearby को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) से थर्ड प्रोवाइडर एप्लिकेशन पार्टि-TPAP) लाइसेंस मिला, जिससे यह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधे UPI सेवाएँ प्रदान कर सके।
- Following NPCI's approval, the company launched the 'PayNearby Saathi' application.
- NPCI की मंजूरी मिलने के बाद कंपनी ने 'PayNearby Saathi' ऐप लॉन्च किया।
- The app integrates BHASHINI, the Government of India-supported AI-driven speech technology platform, allowing users to interact in their preferred language, raise queries, and receive instant responses.
- इस ऐप में BHASHINI को जोड़ा गया है, जो भारत सरकार द्वारा समर्थित AI-संचालित स्पीच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, जिससे उपयोगकर्ता अपनी पसंदीदा भाषा में संवाद कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और तुरंत उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

Ques: Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL) has approved the incorporation of step-down wholly owned subsidiaries in which countries?

Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL) ने किन देशों में स्टेप वाली स्वामित्व पूर्ण डाउन-

है दी मंजूरी को गठन के कंपनियों सहायक?

- A) Singapore and UAE / सिंगापुर और यूएई
- B) Indonesia and Luxembourg / इंडोनेशिया और लक्ज़मबर्ग
- C) UK and Germany / यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी
- D) Indonesia and Singapore / इंडोनेशिया और सिंगापुर
- E) Luxembourg and France / लक्ज़मबर्ग और फ्रांस

Answer: Option B

Explanation / व्याख्या:

- Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL), a wholly owned subsidiary of One97 Communications, has approved the incorporation of two step-down wholly owned subsidiaries in Indonesia and Luxembourg.
- वन97 कम्युनिकेशंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी Paytm Cloud Technologies Ltd (PCTL) ने इंडोनेशिया और लक्ज़मबर्ग में दो स्टेप स्वामित्व पूर्ण डाउन-है। दी मंजूरी को गठन के कंपनियों सहायक वाली
- Up to Rs 25 crore will be invested in each subsidiary, either in one or two tranches.
- प्रत्येक सहायक कंपनी में एक या दो चरणों में अधिकतम 25 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- The transaction is expected to be completed by February 28, 2026.
- यह लेन देन-28 फरवरी 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है।
- Separately, Paytm is diluting its stake in Paytm Arab Payments LLC, its UAE-based subsidiary, through a strategic investment by Abbar Global Opportunities Holdings.
- इसके अलावा, Paytm अपनी यूएई स्थित सहायक कंपनी Paytm Arab Payments LLC में हिस्सेदारी घटा रहा है, जिसमें Abbar Global Opportunities Holdings द्वारा रणनीतिक निवेश किया जा रहा है।

Ques: How much liquidity will the RBI inject into the banking system through OMOs and forex buy-sell swaps?

RBI OMOs और विदेशी मुद्रा खरीद कितनी में प्रणाली बैंकिंग से माध्यम के स्वैप बिक्री-है वाला डालने तरलता?

- A) ₹1 trillion
- B) ₹2 trillion
- C) ₹3 trillion
- D) ₹4 trillion
- E) ₹5 trillion

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India (RBI) announced a fresh round of liquidity measures, including open-market operations (OMOs) and a foreign exchange buy-sell swap, to inject nearly ₹3 trillion into the banking system.
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ओपन (ऑपरेशंस मार्केट-OMOs) और विदेशी मुद्रा खरीद-बिक्री स्वैप सहित तरलता उपायों का नया दौर घोषित किया, जिसके तहत बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹3 ट्रिलियन डाले जाएंगे।
 - RBI will purchase Government of India securities worth ₹2 trillion through OMOs in four tranches of ₹50,000 crore each on 29 December, 5 January, 12 January, and 22 January.
 - RBI 29 दिसंबर, 5 जनवरी, 12 जनवरी और 22 जनवरी को चार ट्रैंचों में प्रत्येक ₹50,000 करोड़ के हिसाब से ₹2 ट्रिलियन के सरकारी प्रतिभूतियां OMO के माध्यम से खरीदेगा।
 - Additionally, RBI will conduct a three-year USD-INR buy-sell swap of \$10 billion on 13 January.
 - इसके अलावा, RBI 13 जनवरी को 3-वर्षीय USD-INR खरीद स्वैप बिक्री-\$10 बिलियन का कार्य करेगा।
 - Net liquidity in the banking system was in deficit by ₹54,852 crore, and RBI has infused ₹1.45 trillion of durable liquidity in December so far.
 - बैंकिंग प्रणाली में शुद्ध तरलता ₹54,852 करोड़ की कमी में थी, और दिसंबर में अब तक RBI ने ₹1.45 ट्रिलियन की स्थायी तरलता डाली है।
-

Ques: 'Pay Later with BharatPe', recently in news, is launched in partnership with which bank?

प्रश्न रहा में समाचारों में ही हाल : 'Pay Later with BharatPe' किस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया गया है?

- A) State Bank of India / स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
- B) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
- C) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
- D) YES Bank / यस बैंक
- E) Axis Bank / एक्सिस बैंक

Answer: Option D

Explanation / व्याख्या:

- BharatPe, in partnership with YES Bank, launched 'Pay Later with BharatPe', an instant Credit on UPI product powered by NPCI.
- भारतपे ने YES बैंक के सहयोग से NPCI द्वारा संचालित UPI आधारित इंस्टेंट क्रेडिट उत्पाद 'Pay Later with BharatPe' लॉन्च किया है।
- The facility offers interest-free credit for up to 45 days, with limits refreshed upon repayment, and flexible EMI options of 3–12 months.
- यह सुविधा 45 दिनों तक ब्याजहै करती प्रदान क्रेडिट मुक्त-, भुगतान के बाद लिमिट रिफ्रेश होती है और 3–12 महीनों की लचीली EMI विकल्प उपलब्ध कराती है।

About YES Bank:

- Established : 2004
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Prashant Kumar
- Tagline : Life Ko Banao Rich

Ques : What recent change did Nepal make regarding carrying Indian currency?

नेपाल ने भारतीय मुद्रा ले जाने को लेकर हाल ही में क्या बदलाव किया है?

- A) Allowed carrying ₹1,000 notes up to ₹50,000 / ₹50,000 तक ₹1,000 के नोट ले जाने की अनुमति
- B) Lifted ban and allowed ₹200 and ₹500 notes up to ₹25,000 / प्रतिबंध हटाकर ₹200 व ₹500 के नोट ₹25,000 तक की अनुमति
- C) Allowed only ₹100 notes without any limit / केवल ₹100 के नोट बिना सीमा के

D) Allowed Indian currency only for Nepali citizens / केवल नेपाली नागरिकों के लिए भारतीय मुद्रा की अनुमति

E) Continued the ban on high-denomination Indian notes / उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों पर प्रतिबंध जारी

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Government of Nepal has lifted its decade-long ban on carrying high-denomination Indian currency.
 - नेपाल सरकार ने उच्च मूल्यवर्ग की भारतीय मुद्रा ले जाने पर लगे लगभग एक दशक पुराने प्रतिबंध को हटा दिया है।
 - Under the revised currency rules, Indian banknotes of ₹200 and ₹500 are permitted.
 - संशोधित मुद्रा नियमों के तहत ₹200 और ₹500 के भारतीय नोटों की अनुमति दी गई है।
 - The maximum limit allowed is ₹25,000 per person.
 - प्रति व्यक्ति अधिकतम सीमा ₹25,000 तय की गई है।
 - The rule applies to both Nepali and Indian citizens and is valid for carrying currency from India to Nepal and from Nepal to India.
 - यह नियम नेपाली और भारतीय दोनों नागरिकों पर लागू होता है तथा भारत से नेपाल और नेपाल से भारत मुद्रा ले जाने की अनुमति देता है।
 - The decision follows amendments made by the Reserve Bank of India to FEMA and the Foreign Exchange Management (Export and Import of Currency) Regulations, 2015.
 - यह निर्णय RBI द्वारा FEMA और विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियम (आयात एवं निर्यात), 2015 में किए गए संशोधनों के बाद लिया गया है।
 - RBI's amendment allows Indian, Nepali, and Bhutanese nationals to carry higher-denomination Indian notes while travelling to and from India.
 - RBI के संशोधन के अनुसार भारतीय, नेपाली और भूटानी नागरिक भारत की यात्रा के दौरान उच्च मूल्यवर्ग के भारतीय नोट ले जा सकते हैं।
-

Ques: The World Bank approved a loan of ₹9,821 crore for which organisation to refinance debt related to the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) project?

विश्व बैंक ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) परियोजना से जुड़े ऋण के पुनर्वित्तपोषण के लिए ₹9,821 करोड़ का ऋण किस संस्था को दिया है?

- A) Indian Railways / भारतीय रेल
- B) Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) / रेल विकास निगम लिमिटेड
- C) Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) / डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
- D) National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) / नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड
- E) Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC) / इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The World Bank has provided a loan of ₹9,821 crore to the Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL).
- विश्व बैंक ने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) को ₹9,821 करोड़ का ऋण प्रदान किया है।
- The loan is routed through the Indian Railway Finance Corporation Limited (IRFC).
- यह ऋण इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRFC) के माध्यम से दिया गया है।
- The objective of the loan is to refinance DFCCIL's existing World Bank currency debt for the Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC) project.
- इस ऋण का उद्देश्य ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (EDFC) परियोजना के लिए DFCCIL के मौजूदा विश्व बैंक मुद्रा ऋण का पुनर्वित्तपोषण करना है।
- The refinancing is expected to improve debt sustainability and support efficient freight transportation infrastructure in India.
- यह पुनर्वित्तपोषण ऋण स्थिरता में सुधार करेगा और भारत में कुशल माल परिवहन अवसंरचना को समर्थन देगा।

Ques: What recent decision did the Reserve Bank of India (RBI) take regarding Phase-II of the Continuous Clearing and Settlement on Realisation (CCSR) under the Cheque Truncation System (CTS)?

आरबीआई ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) के तहत निरंतर क्लियरिंग एवं सेटलमेंट (CCSR) के फेज-II को लेकर हाल ही में क्या निर्णय लिया है?

- A) Implemented Phase-II from 3 January 2026 / 3 जनवरी 2026 से फेज-II लागू किया
- B) Cancelled the CCSR framework permanently / CCSR ढांचे को स्थायी रूप से रद्द कर दिया
- C) Postponed Phase-II implementation until further notice / फेज-II के क्रियान्वयन को अगले आदेश तक स्थगित किया
- D) Reduced cheque settlement time to T+0 immediately / चेक सेटलमेंट समय को तुरंत T+0 कर दिया
- E) Allowed banks to process cheques only after banking hours / बैंकों को केवल बैंकिंग समय के बाद चेक प्रोसेस करने की अनुमति दी

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Reserve Bank of India has postponed the implementation of Phase-II of Continuous Clearing and Settlement on Realisation (CCSR) under the Cheque Truncation System, which was earlier scheduled for 3 January 2026, until further notice.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत निरंतर क्लियरिंग एवं सेटलमेंट (CCSR) के फेज-II के क्रियान्वयन को, जो पहले 3 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित था, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।
- Phase-I, which was launched on 4 October 2025, will continue and enables banks to digitally process and confirm cheques on a continuous basis during working hours.
- 4 अक्टूबर 2025 को शुरू किया गया फेज-I जारी रहेगा, जिसके तहत बैंक कार्य घंटों के दौरान डिजिटल रूप से चेक प्रोसेस और कन्फर्म कर सकते हैं।
- RBI has revised CTS working hours: the cheque presentation session will now run from 9 AM to 3 PM instead of 10 AM to 4 PM.
- आरबीआई ने CTS के कार्य समय में बदलाव किया है, जिसके तहत अब चेक प्रस्तुतिकरण सत्र 10 बजे से 4 बजे के बजाय 9 बजे से 3 बजे तक होगा।
- Banks have been directed to confirm or reject cheques between 9 AM and 7 PM, earlier 10 AM to 7 PM.
- बैंकों को अब 10 बजे से 7 बजे के बजाय 9 बजे से 7 बजे तक चेक की पुष्टि या अस्वीकृति

करने का निर्देश दिया गया है।

- Under Phase-II, the cheque item expiry time was proposed to be reduced to T+3 hours (transaction date plus 3 hours), compared to the existing T+1 or T+2 settlement framework.
- फेज-II के तहत चेक की सेटलमेंट समयसीमा को T+1 या T+2 के बजाय T+3 घंटे देन-लेन) + तारीख की 3 घंटे प्रस्त का करने (ाव था।

Ques: The report titled “Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” has been jointly published by which of the following institutions?

“Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” शीर्षक वाली रिपोर्ट निम्नलिखित में से किन संस्थानों द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है?

- A) Asian Development Bank, World Trade Organization, World Economic Forum / एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, विश्व आर्थिक मंच
- B) International Monetary Fund, World Bank, OECD / अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, OECD
- C) United Nations, World Bank, WTO / संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, WTO
- D) World Economic Forum, OECD, UNDP / विश्व आर्थिक मंच, OECD, UNDP
- E) Asian Development Bank, IMF, World Bank / एशियाई विकास बैंक, IMF, विश्व बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The report “Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” is jointly published by the Asian Development Bank (ADB), World Trade Organization (WTO), and World Economic Forum (WEF).
- “Rewiring GVCs in a Changing Global Economy” रिपोर्ट एशियाई विकास बैंक (ADB), विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है।
- GVCs refer to Global Value Chains, where different stages of production occur across multiple countries, with each stage adding value.
- GVCs का अर्थ ग्लोबल वैल्यू चेन है, जिसमें उत्पादन के विभिन्न चरण अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं जोड़ता मूल्य चरण प्रत्येक और हैं होते

- The report highlights that globalisation is being rewired rather than reversed, driven by technological changes, green transition, and shifting geopolitical conditions.
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्वीकरण उलट नहीं रहा है, बल्कि तकनीकी बदलाव, हरित संक्रमण और बदलती भूपरिस्थिति राजनीतिक-यों के कारण नए सिरे से ढल रहा है।
- GVCs account for 46.3% of global trade, slightly lower than the 2022 peak of 48%, indicating resilience despite global challenges.
- वैश्विक व्यापार में GVCs की हिस्सेदारी 46.3% है, जो 2022 के 48% के शिखर से थोड़ी कम है, फिर भी यह लचीलापन दर्शाती है।
- India has strengthened its integration into GVCs, driven mainly by strong growth in digital services exports, and is among the top 10 value-adding economies globally.
- भारत ने डिजिटल सेवा निर्यात की मजबूत वृद्धि के कारण GVCs में अपनी भागीदारी को मजबूत किया है और वह विश्व की शीर्ष 10 मूल्य है। शामिल में अर्थव्यवस्थाओं वर्धक-

Ques: What is the purpose of the centralized portal launched by the National Payments Corporation of India (NPCI)?

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा शुरू किए गए केंद्रीकृत पोर्टल का उद्देश्य क्या है?

- A) To allow international UPI payments / अंतरराष्ट्रीय UPI भुगतान की अनुमति देना
- B) To track failed UPI transactions only / केवल असफल UPI लेनदेन को ट्रैक करना
- C) To view, manage, and revoke UPI Autopay standing instructions from one platform / एक ही प्लेटफॉर्म से UPI ऑटोपे स्थायी निर्देशों को देखना, प्रबंधित करना और रद्द करना
- D) To provide loans through UPI / UPI के माध्यम से ऋण प्रदान करना
- E) To increase UPI transaction charges / UPI लेनदेन शुल्क बढ़ाना

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The National Payments Corporation of India (NPCI) has launched a centralized portal (npci.org.in) to enable users to view, manage, and revoke all UPI Autopay standing instructions from a single platform.

- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने npci.org.in नामक एक केंद्रीकृत पोर्टल शुरू किया है, जिससे उपयोगकर्ता एक ही प्लेटफॉर्म से सभी UPI ऑटोपे स्थायी निर्देशों को देख, प्रबंधित और रद्द कर सकते हैं।
- All UPI ecosystem members, including banks and payment service providers, must implement these reforms by December 31, 2025, to enhance consumer protection and transparency.
- उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी UPI इकोसिस्टम सदस्य, जिनमें बैंक और भुगतान सेवा प्रदाता शामिल हैं, को 31 दिसंबर 2025 तक इन सुधारों को लागू करना अनिवार्य है।
- In November 2025, the top 10 banks processed 926 million UPI Autopay transactions, up from 530.5 million in November 2024, reflecting rapid growth in recurring digital payments.
- नवंबर 2025 में शीर्ष 10 बैंकों ने 926 मिलियन UPI ऑटोपे लेनदेन संसाधित किए, जो नवंबर 2024 के 530.5 मिलियन से काफी अधिक हैं, और यह आवर्ती डिजिटल भुगतानों में तेज वृद्धि को दर्शाता है।
- State Bank of India (SBI) emerged as the largest processor with 290 million UPI Autopay transactions, while Airtel Payments Bank recorded the fastest growth, rising from 25.6 million to 89.7 million transactions within a year.
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 290 मिलियन UPI ऑटोपे लेनदेन के साथ सबसे बड़ा प्रोसेसर बना, जबकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की, जिसके लेनदेन एक वर्ष में 25.6 मिलियन से बढ़कर 89.7 मिलियन हो गए।

About NPCI :

- Established : 2008
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : Dilip Asbe

Ques: Which bank has partnered with Fyno to deploy a unified customer communication platform?

एकीकृत ग्राहक संचार प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए Fyno ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है?

- A) Kerala Grameena Bank / केरल ग्रामीण बैंक
- B) Punjab National Bank / पंजाब नेशनल बैंक
- C) Canara Bank / केनरा बैंक

D) Bank of Baroda / बैंक ऑफ बड़ौदा

E) Indian Bank / इंडियन बैंक

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Fyno has partnered with Kerala Grameena Bank (KGB) to deploy a unified customer communication platform.
- Fyno ने केरल ग्रामीण बैंक (KGB) के साथ एकीकृत ग्राहक संचार प्लेटफॉर्म को लागू करने के लिए साझेदारी की है।
- Fyno is an intelligent communications hub designed for banks and financial services institutions.
- Fyno बैंकों और वित्तीय सेवा संस्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन हब है।
- The platform helps manage, govern, and automate customer communications across the banking network.
- यह प्लेटफॉर्म बैंकिंग नेटवर्क में ग्राहक संचार के प्रबंधन, शासन और स्वचालन में मदद करता है।
- Key features include centralized management of all customer communications and the ability to create, manage, and update communication templates consistently.
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में सभी ग्राहक संचार का केंद्रीकृत प्रबंधन और संचार टेम्पलेट्स को बनाने, प्रबंधित करने व अपडेट करने की सुविधा शामिल है।
- The Chief Executive Officer and Co-Founder of Fyno is Aniketh Jain.
- Fyno के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सह-जैन अनिकेत संस्थापक-

Ques: Which company has launched the health insurance product “Galaxy Twin 360” for young adults?

युवा वयस्कों के लिए “Galaxy Twin 360” स्वास्थ्य बीमा उत्पाद किस कंपनी ने लॉन्च किया है?

- A) Star Health Insurance / स्टार हेल्थ इंश्योरेंस
- B) HDFC ERGO Health Insurance / एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस
- C) Care Health Insurance / केयर हेल्थ इंश्योरेंस

- D) ICICI Lombard Health Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस
E) Galaxy Health Insurance / गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Galaxy Health Insurance, promoted by V Jagannathan and TVS Group's Venu Srinivasan, has launched a new health insurance product named "Galaxy Twin 360".
- वी ने इंश्योरेंस हेल्थ गैलेक्सी प्रवर्तित द्वारा श्रीनिवासन वेणु के गुप एसटीवी और जगन्नाथन . "Galaxy Twin 360" नामक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है।
- The product is targeted at young adults aged between 18 and 45 years.
- यह उत्पाद 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवा वयस्कों को लक्षित करता है।
- Galaxy Twin 360 is available under three plans: Core, Max, and Ultra.
- Galaxy Twin 360 तीन योजनाओं—Core, Max और Ultra—में उपलब्ध है।
- Key features include IPD (Inpatient Department) coverage, high-value OPD (Outpatient Department) benefits, and wellness services.
- इसकी प्रमुख विशेषताओं में आईपीडी कवर (डिपार्टमेंट इनपेशेंट), उच्च ओपीडी मूल्य-हैं। शामिल सेवाएँ वेलनेस और लाभ (डिपार्टमेंट आउटपेशेंट)

Ques: What change has SEBI made regarding eligibility for a Basic Services Demat Account (BSDA)?

बेसिक सर्विसेज डिमैट अकाउंट (BSDA) की पात्रता को लेकर SEBI ने क्या बदलाव किया है?

- A) Increased the BSDA holding limit to ₹20 lakh / BSDA होल्डिंग सीमा को ₹20 लाख तक बढ़ाया
- B) Included ZCZP bonds in valuation threshold / ZCZP बॉन्ड को मूल्यांकन सीमा में शामिल किया
- C) Excluded ZCZP bonds and delisted securities from valuation threshold / ZCZP बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज को मूल्यांकन सीमा से बाहर किया
- D) Abolished BSDA accounts altogether / BSDA खातों को पूरी तरह समाप्त कर दिया
- E) Made BSDA mandatory for all investors / सभी निवेशकों के लिए BSDA अनिवार्य कर दिया

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has decided to exclude Zero Coupon Zero Principal (ZCZP) bonds and delisted securities from the valuation threshold used to determine eligibility for a Basic Services Demat Account (BSDA).
 - भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने BSDA की पात्रता तय करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन सीमा से ज़ीरो कूपन ज़ीरो प्रिंसिपल (ZCZP) बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज को बाहर करने का निर्णय लिया है।
 - As per the revised norms, the value of ZCZP bonds and delisted securities will not be counted while checking whether an investor's holdings are within the ₹10 lakh BSDA limit.
 - संशोधित नियमों के अनुसार, ₹10 लाख की BSDA सीमा की जांच करते समय ZCZP बॉन्ड और डीलिस्टेड सिक्योरिटीज के मूल्य को शामिल नहीं किया जाएगा।
 - These changes will come into effect from March 31, 2026, and are aimed at supporting small investors by allowing them to continue availing BSDA benefits despite such holdings.
 - ये बदलाव 31 मार्च 2026 से लागू होंगे और छोटे निवेशकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से किए गए हैं, ताकि वे ऐसे निवेश होने के बावजूद BSDA के लाभ ले सकें।
 - A Basic Services Demat Account (BSDA) is a simplified demat account introduced by SEBI in 2012 to reduce maintenance charges for investors with relatively small portfolios.
 - बेसिक सर्विसेज डिमैट अकाउंट (BSDA) SEBI द्वारा 2012 में शुरू किया गया एक सरल डिमैट खाता है, जिसका उद्देश्य छोटे पोर्टफोलियो वाले निवेशकों के लिए रखरखाव शुल्क कम करना है।
-

Ques: From which date will Oman's first polymer one-rial banknote start circulating?

ओमान का पहला पॉलिमर वनआएगा में प्रचलन से तिथि किस बैंकनोट रियाल-?

- A) January 1, 2025
- B) January 11, 2026
- C) March 15, 2026
- D) July 1, 2026

E) December 31, 2026

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- Oman has introduced its first-ever polymer one-rial banknote to enhance durability and security.
 - ओमान ने अधिक टिकाऊपन और सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से अपना पहला पॉलिमर वन-रियाल बैंकनोट जारी किया है।
 - The new polymer banknote will officially enter circulation from January 11, 2026.
 - नया पॉलिमर बैंकनोट 11 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से प्रचलन में आएगा।
 - Polymer banknotes last longer and are more resistant to wear and tear compared to traditional paper notes.
 - पॉलिमर बैंकनोट पारंपरिक कागजी नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं और जल्दी खराब नहीं होते।
 - The banknote incorporates advanced security features to prevent counterfeiting.
 - जालसाजी रोकने के लिए इस बैंकनोट में उन्नत सुरक्षा विशेषताएँ शामिल की गई हैं।
 - Its design showcases Oman's cultural heritage and economic achievements.
 - इसके डिज़ाइन में ओमान की सांस्कृतिक विरासत और आर्थिक उपलब्धियों को दर्शाया गया है।
 - This initiative aligns Oman with global best practices in modern currency design.
 - यह पहल ओमान को आधुनिक मुद्रा डिज़ाइन की वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाती है।
-

Ques: Which regulator has simplified the procedure for issuance of duplicate securities by doubling the monetary threshold for simplified documentation to ₹10 lakh?

डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए ₹10 लाख तक की सीमा बढ़ाने का निर्णय किस नियामक ने लिया है?

A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक

B) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

C) Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) / भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

D) Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) / पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

E) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has simplified the procedure for issuance of duplicate securities by increasing the monetary threshold for simplified documentation from ₹5 lakh to ₹10 lakh.
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने डुप्लीकेट प्रतिभूतियों के निर्गमन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सरलीकृत दस्तावेज़ीकरण की सीमा ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख कर दी है।
- The decision follows a consultation paper issued in November 2025, aimed at improving ease of investor services and bringing uniformity in procedures.
- यह निर्णय नवंबर 2025 में जारी परामर्श पत्र के बाद लिया गया, जिसका उद्देश्य निवेशक सेवाओं को आसान बनाना और प्रक्रियाओं में एकरूपता लाना है।
- Investors holding securities valued up to ₹10 lakh will now need to submit fewer documents for reissuance of lost or damaged securities.
- ₹10 लाख तक मूल्य की प्रतिभूतियां रखने वाले निवेशकों को अब खोई या क्षतिग्रस्त प्रतिभूतियों के पुनः निर्गमन के लिए कम दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
- For securities up to ₹10,000, investors can submit a simple undertaking on plain paper.
- ₹10,000 तक की प्रतिभूतियों के लिए निवेशक साधारण कागज़ पर एक साधारण अंडरटेकिंग जमा कर सकते हैं।
- For securities above ₹10,000 and up to ₹10 lakh, only a standard Affidavit-cum-Indemnity Bond on appropriate non-judicial stamp paper is required.
- ₹10,000 से अधिक और ₹10 लाख तक की प्रतिभूतियों के लिए उपयुक्त गैर स्टाम्प न्यायिक-क्ष-सह-शपथपत्र मानक केवल पर पेपरतिपूर्ति बांड की आवश्यकता होगी।
- For securities exceeding ₹10 lakh, additional safeguards such as FIRs, court-related documents, and mandatory newspaper advertisements by listed companies will continue to apply.

- ₹10 लाख से अधिक की प्रतिभूतियों के मामलों में एफआईआर, न्यायालय से संबंधित दस्तावेज़ और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनिवार्य समाचार अतिरिक्त जैसी विज्ञापन पत्र-रहेंगी। लागू शर्तें सुरक्षा

Ques: Which company received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India to commence operations as a Non-Banking Financial Company (NBFC)?

भारतीय रिज़र्व बैंक से एनबीएफसी के रूप में कार्य शुरू करने के लिए प्रमाणपत्र (CoR) किस कंपनी को प्राप्त हुआ?

- A) Aryaman Finance (India) Limited / आर्यमन फाइनेंस लिमिटेड (इंडिया)
- B) Bajaj Finance Limited / बजाज फाइनेंस लिमिटेड
- C) Shriram Finance Limited / श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड
- D) Tata Capital Limited / टाटा कैपिटल लिमिटेड
- E) L&T Finance Limited / एल एंड टी फाइनेंस लिमिटेड

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Aryaman Finance (India) Limited (AFIL) has received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India (RBI) to start the business of a Non-Banking Financial Company (NBFC).
- आर्यमन फाइनेंस) लिमिटेड (इंडिया)AFIL को गैर) कंपनी वित्तीय बैंकिंग-NBFC) के रूप में व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त हुआ है।
- The RBI grants NBFC registration under Section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- आरबीआई एनबीएफसी का पंजीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के तहत प्रदान करता है।
- Following this approval, AFIL will operate as a Type-II NBFC-ND-ICC (Non-Deposit Taking – Investment and Credit Company).
- इस स्वीकृति के बाद, AFIL टाइप-II NBFC-ND-ICC (गैर वाली करने स्वीकार जमा-- निवेश एवं ऋण कंपनी कार्य में रूप के (करेगी)।

Ques: As per the RBI report, what was the total deposits of payments banks in India as of March 2025?

आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत में पेमेंट्स बैंकों की कुल जमा राशि कितनी थी?

- A) ₹18,000 crore
- B) ₹22,450 crore
- C) ₹25,605 crore
- D) ₹28,900 crore
- E) ₹30,000 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- According to the RBI report, deposits in India's payments banks increased by 57% year-on-year to ₹25,605 crore as of March 2025.
 - आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत के पेमेंट्स बैंकों की जमा राशि साल-साल-दर 57% बढ़कर ₹25,605 करोड़ हो गई।
 - As of March 2025, a total of six payments banks were operational in India with 81 branches across the country.
 - मार्च 2025 तक भारत में कुल 6 पेमेंट्स बैंक कार्यरत थे, जिनकी 81 शाखाएँ थीं।
 - Deposits, including savings and current accounts, accounted for 68.1% of the total liabilities of payments banks.
 - जमा राशि का देनदारियों कुल की बैंकों पेमेंट्स (खाते चालू एवं बचत) 68.1% हिस्सा रही।
 - On the asset side, investments were mainly in Statutory Liquidity Ratio (SLR) securities due to restrictions on lending.
 - ऋण देने पर प्रतिबंध के कारण परिसंपत्ति पक्ष में मुख्य रूप से वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।
 - Payments banks remained profitable for the third consecutive year in FY25, indicating improving financial stability.
 - FY25 में पेमेंट्स बैंक लगातार तीसरे वर्ष लाभ में रहे, जो उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाता है।
-

Ques: Which Russian bank has been authorised by India's Ministry of Commerce and Industry to import gold for FY 2025–26 under the Foreign Trade Policy 2023?

विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सोना आयात करने हेतु भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने किस रूसी बैंक को अधिकृत किया है?

- A) VTB Bank / वीटीबी बैंक
- B) Gazprombank / गज़प्रोमबैंक
- C) Sber Bank / स्बर बैंक
- D) Alfa-Bank / अल्फा बैंक
- E) Rosbank / रोसबैंक

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Commerce and Industry has added Russia's Sber Bank to the list of banks authorised to import gold for FY 2025–26, expanding the authorised importer base.
 - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2025–26 के लिए सोना आयात करने हेतु रूस के स्बर बैंक को अधिकृत बैंकों की सूची में शामिल किया है।
 - The authorisation has been granted under the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time.
 - यह प्राधिकरण समय) नीति व्यापार विदेश संशोधित पर समय-FTP) 2023 के तहत दिया गया है।
 - Sber Bank's authorisation is valid from June 25, 2025, to March 31, 2026, and is restricted exclusively to gold imports meant for domestic consumption.
 - स्बर बैंक की अनुमति 25 जून 2025 से 31 मार्च 2026 तक मान्य है और यह केवल घरेलू उपभोग के लिए सोना आयात करने तक सीमित है।
 - With this inclusion, Sber Bank becomes the third bank—after Indian Overseas Bank and Union Bank of India—authorised to import only gold during FY 2025–26.
 - इस शामिल किए जाने के साथ, स्बर बैंक वित्त वर्ष 2025–26 में केवल सोना आयात करने के लिए अधिकृत तीसरा बैंक बन गया है; इससे पहले इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को यह अनुमति दी गई थी।
-

Ques: As per the RBI report, what was the total number of ATMs in India as of March 31, 2025?

RBI रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भारत में ATM की कुल संख्या कितनी थी?

- A) 2,53,417
- B) 2,48,900
- C) 2,51,057
- D) 2,60,000
- E) 2,45,120

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- According to the RBI report, the total number of ATMs in India declined to 2,51,057 as of March 31, 2025, from 2,53,417 a year earlier.
- RBI रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भारत में ATM की कुल संख्या घटकर 2,51,057 रह गई, जो एक वर्ष पहले 2,53,417 थी।
- The decline in ATM numbers is attributed to the rapid rise in digital payments and increased digitisation of banking services.
- ATM की संख्या में यह गिरावट डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं के डिजिटलीकरण में वृद्धि के कारण हुई है।
- Private sector banks saw a decline in ATMs to 77,117 from 79,884 in the previous year.
- निजी क्षेत्र के बैंकों के ATM घटकर 77,117 रह गए, जो पिछले वर्ष 79,884 थे।
- Public sector banks' ATMs also fell to 1,33,544 from 1,34,694.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ATM भी घटकर 1,33,544 हो गए, जो पहले 1,34,694 थे।
- Banks have been shutting down offsite ATMs as customer dependence on cash transactions continues to decline.
- ग्राहकों की नकद लेन ऑफसाइट बैंक कारण के होने कम निर्भरता पर देन-ATM बंद कर रहे हैं।
- Despite the decline in ATMs, the number of bank branches increased by over 2%, led mainly by public sector banks.
- ATM में गिरावट के बावजूद बैंक शाखाओं की संख्या 2% से अधिक बढ़ी, जिसमें सार्वजनिक बैंकों की प्रमुख भूमिका रही।
- As of March 31, 2025, India had around 1.64 lakh bank branches, reflecting a year-on-year growth of 2.8%.

- 31 मार्च 2025 तक भारत में लगभग 1.64 लाख बैंक शाखाएँ थीं, जो 2.8% की वार्षिक वृद्धि दर्शाती हैं।
- The number of white-label ATMs increased to 36,216 from 34,602, indicating expansion in this segment.
- व्हाइट लेबल-ATM की संख्या बढ़कर 36,216 हो गई, जो पहले 34,602 थी।

Ques: Which scheme launched in Union Budget 2024–25 aims to promote early savings and long-term financial security for minors in India?

भारत में नाबालिगों के लिए प्रारंभिक बचत और दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2024–25 के केंद्रीय बजट में कौनगई की शुरू योजना सी-?

- A) Atal Pension Yojana / अटल पेंशन योजना
- B) Sukanya Samridhi Yojana / सुकन्या समृद्धि योजना
- C) Public Provident Fund / सार्वजनिक भविष्य निधि
- D) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana / प्रधानमंत्री वय वंदना योजना
- E) National Pension System Vatsalya / राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The National Pension System Vatsalya (NPS Vatsalya) was announced in the Union Budget 2024–25 on 23 July 2024 and launched by Finance Minister Nirmala Sitharaman.
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य (NPS Vatsalya) की घोषणा 23 जुलाई 2024 को केंद्रीय बजट 2024–25 में की गई और इसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया।
- The scheme is administered and regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- इस योजना का संचालन और नियमन पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है।
- It is a saving-cum-pension scheme for all minor citizens up to 18 years, with the account opened in the name of the minor and operated by a parent or guardian.
- यह 18 वर्ष तक के सभी नाबालिग नागरिकों के लिए एक बचत-पेंशन योजना है, जिसमें खाता नाबालिग के नाम पर खोला जाता है और अभिभावक द्वारा संचालित किया जाता है।

- The minimum contribution is ₹1,000 to open the account and ₹1,000 per annum thereafter, with no upper limit on maximum contribution.
- खाता खोलने के लिए न्यूनतम योगदान ₹1,000 और उसके बाद प्रति वर्ष ₹1,000 है, जबकि अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है।
- At the age of 18, the account automatically converts into an NPS Tier-I (All Citizen) account, subject to fresh KYC within three months.
- 18 वर्ष की आयु पर यह खाता स्वतः NPS टियर-I (ऑल सिटीजन हो परिवर्तित में खाते (है जाता, जिसके लिए तीन माह के भीतर नया KYC आवश्यक है।

Ques: According to the RBI's Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25, by how much did the banking system's balance sheet expand during 2024–25?

RBI की बैंकिंग में रुझान और प्रगति रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का बैलेंस शीट कितने प्रतिशत बढ़ा?

- A) 9.5%
- B) 10.2%
- C) 11.2%
- D) 12.0%
- E) 12.5%

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- As per the RBI's Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25, the banking system's balance sheet expanded by 11.2% during the year.
- RBI की बैंकिंग में रुझान और प्रगति रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का बैलेंस शीट 11.2% बढ़ा।
- The total size of the banking system's balance sheet reached ₹312.2 lakh crore in 2024–25.
- 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का कुल बैलेंस शीट आकार ₹312.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया।
- During the same period, bank deposits registered a growth of 11.1%.
- इसी अवधि में बैंक जमाओं (Deposits) में 11.1% की वृद्धि दर्ज की गई।
- Bank credit, including loans and advances, increased by 11.5%, broadly

matching the pace of deposit growth.

- बैंक ऋण (Loans एवं Advances) में 11.5% की वृद्धि हुई, जो जमा वृद्धि के लगभग समान रही।
- Overall, the report reflects steady and balanced growth in India's banking sector.
- कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट भारत के बैंकिंग क्षेत्र में स्थिर और संतुलित वृद्धि को दर्शाती है।

Ques: Which institution provided a ₹300 crore loan to the Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) issued by Grihum Housing Finance Limited, marking its first-ever RMBS investment in India?

भारत में पहली बार RMBS निवेश करते हुए, गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी रेज़िडेंशियल मॉर्गेज) सिक्योरिटीज़ बैकड-RMBS) को ₹300 करोड़ का ऋण किस संस्था ने प्रदान किया?

- A) Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक
- B) World Bank / विश्व बैंक
- C) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
- D) New Development Bank (NDB) / न्यू डेवलपमेंट बैंक
- E) International Finance Corporation (IFC) / अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The International Finance Corporation (IFC) has provided a loan of ₹300 crore (about USD 30 million) to the Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) issued by Grihum Housing Finance Limited.
- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) ने गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी रेज़िडेंशियल मॉर्गेज) सिक्योरिटीज़ बैकड-RMBS) को ₹300 करोड़ (लगभग) 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर (है। किया प्रदान ऋण का
- This investment marks IFC's first-ever RMBS investment in India.
- यह भारत में IFC का पहला RMBS निवेश है।
- The International Finance Corporation was established in 1956 and is headquartered in Washington, D.C., United States.
- अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन

डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है।

- IFC focuses on private sector development in emerging economies by providing investments, advisory services, and asset management.
- IFC उभरती अर्थव्यवस्थाओं में निजी क्षेत्र के विकास के लिए निवेश, परामर्श सेवाएँ और परिसंपत्ति प्रबंधन प्रदान करता है।
- The current Managing Director of IFC is Makhtar Diop.
- IFC के वर्तमान प्रबंध निदेशक मख्तार दियोप हैं।

Ques: As per RBI, how many Urban Co-operative Banks (UCBs) were operational at the end of FY25?

RBI के अनुसार FY25 के अंत में कितने शहरी सहकारी बैंक (UCBs) कार्यरत थे?

- A) 1,472
- B) 1,463
- C) 1,457
- D) 1,489
- E) 1,426

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- According to the RBI's *Report on Trend and Progress of Banking in India*, the number of Urban Co-operative Banks (UCBs) declined by 15 during FY25, bringing the total down to 1,457.
- RBI की *ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया* रिपोर्ट के अनुसार FY25 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 15 घटकर 1,457 रह गई।
- The decline in the number of UCBs was mainly due to mergers and cancellation of licences.
- UCBs की संख्या में यह गिरावट मुख्य रूप से विलय और लाइसेंस रद्द होने के कारण हुई।
- During FY25, a total of 7 mergers of UCBs were carried out, with 6 mergers in Maharashtra and 1 in Telangana.
- FY25 में UCBs के कुल 7 विलय किए गए, जिनमें से 6 महाराष्ट्र में और 1 तेलंगाना में हुआ।
- In comparison, FY24 witnessed 6 mergers of Urban Co-operative Banks.
- तुलना में FY24 के दौरान UCBs के 6 विलय हुए थे।
- The RBI initiated the consolidation process of UCBs in 2004–05, focusing on

amalgamation of weak banks and closure of unviable ones.

- RBI ने 2004–05 में UCBs के समेकन की प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें कमजोर बैंकों का विलय और अव्यवहारिक बैंकों को बंद करना शामिल है।
- As a result of this long-term consolidation, the total number of UCBs declined steadily from 1,926 in March 2004 to 1,457 in March 2025.
- इस दीर्घकालिक समेकन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप मार्च 2004 में 1,926 से घटकर मार्च 2025 में UCBs की संख्या 1,457 रह गई।

Ques: Which Government Security has been announced for re-issue by the Government of India through a price-based auction in January 2026?

जनवरी 2026 में मूल्यके नीलामी आधारित- माध्यम से भारत सरकार द्वारा किस सरकारी प्रतिभूति के पुनः निर्गम है गई की घोषणा की (इश्यू-री)?

- A) 6.48% Government Security 2035
- B) 6.18% Government Security 2033
- C) 7.10% Government Security 2034
- D) 6.95% Government Security 2036
- E) 5.89% Government Security 2032

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India has announced the re-issue of “6.48% Government Security 2035” for a notified amount of ₹32,000 crore through a price-based auction using the multiple price method.
- भारत सरकार ने ₹32,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए बहु तहत के पद्धति मूल्य-से माध्यम के नीलामी आधारित-मूल्य “6.48% सरकारी प्रतिभूति 2035” के पुनः निर्गम की घोषणा की है।
- The Government has the option to retain additional subscription of up to ₹2,000 crore against this security.
- सरकार के पास इस प्रतिभूति के विरुद्ध ₹2,000 करोड़ तक की अतिरिक्त सदस्यता बनाए रखने का विकल्प है।
- The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, Mumbai Office, on January 02, 2026.
- यह नीलामी 02 जनवरी 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई कार्यालय द्वारा आयोजित की

जाएगी।

- Up to 5% of the notified amount will be allotted to eligible individuals and institutions under the Non-Competitive Bidding Facility scheme.
- अधिसूचित राशि का अधिकतम 5% गैर सुविधा बोली प्रतिस्पर्धी-योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा।
- Both competitive and non-competitive bids must be submitted electronically through the RBI Core Banking Solution (E-Kuber system).
- प्रतिस्पर्धी और गैरबोल की प्रकार दोनों प्रतिस्पर्धी-ियां आरबीआई के कोर बैंकिंग समाधान जाएंगी। की प्रस्तुत से रूप इलेक्ट्रॉनिक से माध्यम के (प्रणाली कुबेर-ई)
- The security will also be eligible for “When Issued” trading as per RBI guidelines issued on July 24, 2018, and amended from time to time.
- यह प्रतिभूति आरबीआई द्वारा 24 जुलाई 2018 को जारी (संशोधित पर समय-समय) अनुसार के दिशानिर्देशों “व्हेन इश्यूड” ट्रेडिंग के लिए भी पात्र होगी।

Ques: By when does the Unique Identification Authority of India (UIDAI) plan to expand the total number of Aadhaar Seva Kendras to 473 across India? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) कब तक पूरे भारत में आधार सेवा केंद्रों की संख्या 473 करने की योजना बना रहा है?

- A) September 2025
- B) December 2025
- C) September 2026
- D) March 2027
- E) June 2027

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Unique Identification Authority of India (UIDAI) has inaugurated a new Aadhaar Seva Kendra (ASK) at Mangaluru in Dakshina Kannada district of Karnataka.
- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु में एक नया आधार सेवा केंद्र (ASK) शुरू किया है।
- UIDAI has announced plans to open a total of 22 Aadhaar Seva Kendras across Karnataka.

- UIDAI कर्नाटक में कुल 22 आधार सेवा केंद्र खोलने की योजना बना रहा है।
- The total number of Aadhaar Seva Kendras across India will be expanded to 473 by September 2026 to improve accessibility and service delivery.
- देशभर में आधार सेवा केंद्रों की कुल संख्या बढ़ाकर सितंबर 2026 तक 473 कर दी जाएगी, जिससे नागरिकों की पहुंच और सेवा वितरण में सुधार होगा।
- Aadhaar Seva Kendras are full-service centres that provide Aadhaar enrolment, biometric updates, and demographic correction services, especially for adults.
- आधार सेवा केंद्र पूर्ण हैं होते केंद्र सेवा-, जो आधार नामांकन, बायोमेट्रिक अपडेट और जनसांख्यिकीय सुधार जैसी सेवाएँ प्रदान करते हैं, विशेष रूप से वयस्कों के लिए।

